

भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड,
भोपालपानी, पोस्ट-बड़ासी, देहरादून।

5248

संख्या /मुख्य/ खनन/ 77/ सोपस्टोन/ बागे/ भूखनि०५०/ 2016-17,

दिनांक 25 सप्तं दिसम्बर, 2022

कार्यालय-ज्ञाप

श्री कान्ती लाल साह पुत्र श्री गिरधारी लाल साह निवासी पिण्डारी रोड, तहसील व जिला बागेश्वर के पक्ष में औद्योगिक विकास अनुभाग-1 उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 361/VII-I/2019/1(18)/18, दिनांक 14 फरवरी 2019 के द्वारा जनपद व तहसील बागेश्वर के ग्राम नायल/सुनेरी के क्षेत्रान्तर्गत आवेदित कुल 5.250 हैं। भूमि के सापेक्ष कुल 2.704 हैं। भूमि में खनिज सोपस्टोन का 25 वर्ष की अवधि हेतु आशय पत्र (Letter of Intent) पर स्वीकृत खनिज सोपस्टोन के खनन पट्टे पर क्षेत्रफल की खनन योजना एवं उत्तरोत्तर खान बन्द करने की योजना कार्यालय ज्ञाप संख्या 1762/खनन/गौण खनिज-माईनिंग प्लान/26/भूखनि०५०/2015-16, दिनांक 31 अक्टूबर, 2015 तथा उत्तराखण्ड शासन 1589/VII-I/2015/68-ख/2015 दिनांक 31 जुलाई, 2015 यथा संशोधित कार्यालय ज्ञाप संख्या 844/VII-I/2015/68-ख/2015 दिनांक 07 अक्टूबर, 2015 द्वारा जारी उत्तराखण्ड गौण खनिज नीति-2015 के अनुसार उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली 2001 के नियम 34 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते प्रस्तर-3(दो)(1) एवं उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली 2001 के नियम 34 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते प्रस्तुत खनन योजना एवं उत्तरोत्तर खान बन्द करने की योजना का वैज्ञानिक, तकनीकी एवं पर्यावरण सुरक्षा के दृष्टिकोण से खनन योजना एवं उत्तरोत्तर खान बन्द करने की योजना को वैज्ञानिक, तकनीकी एवं पर्यावरण सुरक्षा के दृष्टिकोण से खनन योजना एवं उत्तरोत्तर खान बन्द करने की योजना का अनुमोदन निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन हेतु प्रस्तुत खनन योजना एवं उत्तरोत्तर खान बन्द करने की योजना का अनुमोदन निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन किया जाना प्रस्तावित है :-

शर्त/प्रतिबन्ध:-

- प्रस्तुत खनन योजना का अनुमोदन खनन पट्टे के पंजीकरण के दिनांक से अगामी 05 वर्ष की अवधि हेतु किया जा रहा है।
- किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि दस्तावेज में दी गई, उपलब्ध कराई गई सूचनाएं असत्य अथवा गलत ढंग से दर्शायी गई हैं, तो अनुमोदित खनन योजना का अनुमोदन तत्काल प्रभाव से स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।
- खान एवं खनिज (विकास एवं विनियम) अधिनियम 1957 एवं उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली-2001 के अन्तर्गत अपेक्षित कोई सूचना/विषय वस्तु का संगुप्त रखना/छिपाना यदि पाया जाता है और उसके सुधार हेतु कोई प्रस्ताव भी नहीं दिया जाता है, तो खनन योजना एवं उत्तरोत्तर खान बन्द करने की योजना का अनुमोदन तुरन्त प्रभाव से वापस लेना माना जायेगा।
- खनन कार्य एवं खनिजों के खनिज अन्वेषण/खनिज भण्डारण/खनिज का आंकलन एवं सत्यापन अनुमोदित खनन योजना के अनुसार किया जाना होगा। अनुमोदित खनन योजना एवं उत्तरोत्तर खान बन्द करने की योजना का अनुपालन न किये जाने की अनुसार खनन योजना एवं खनिज (विकास एवं विनियम) अधिनियम 1957 एवं उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली-2001 के अनुसार कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
- आवेदक द्वारा खनन पट्टा स्वीकृति से पूर्ण मशीनीकृत माइनिंग हेतु रु 2.00 लाख बैंक गारन्टी निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म मशीनीकृत हेतु निदेशक के पक्ष में प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
- आवेदक द्वारा औद्योगिक विकास अनुभाग-1 उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 361/VII-I/2019/1(18)/18, दिनांक 14 फरवरी 2019 निर्गत आशय पत्र (Letter of Intent) की शर्त संख्या-4 के अनुसार आवेदक द्वारा पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना का 03/2014 दिनांक 07 अक्टूबर 2014 के क्रम में जारी शासनादेश सं 1621/VII-I/212-ख/2014 दिनांक 17 दिसम्बर, 2014 के अनुसार पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त किया जाना होगा एवं तदनुसार पर्यावरणीय अनुमति की समर्त शर्तों का अनुपालन किया जायेगा।
- कार्यालय ज्ञाप संख्या 361/VII-I/2019/1(18)/18, दिनांक 14 फरवरी 2019 के द्वारा निर्गत आशय पत्र की समर्त शर्तों का अनुपालन आशय पत्र निर्गत के दिनांक 14 फरवरी 2019 से अगामी 06 माह अर्थात् 13 अगस्त 2019 तक

की जानी थी जिसमें वर्तमान तक लगभग 03 वर्ष 05 माह का विलम्ब हो चुका है अगर शासन द्वारा उक्त आशय पत्र की अग्रेतर समयावधि नहीं बढ़ायी जाती है तो यह खनन योजना स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी।

8. यह खनन योजना अन्य किसी अधिनियम जो कि खान या क्षेत्र पर लागू होते हैं या समय-समय पर राज्य सरकार या केन्द्र सरकार या अन्य किसी सक्षम द्वारा प्रख्यापित किये जाते हैं, को छोड़कर अनुमोदित की जाती है।
9. यह खनन योजना वन (संरक्षण) अधिनियम-1980, वन संरक्षण नियमावली 1981 और अन्य सम्बन्धित अधिनियम और नियमावली, आदेश और दिशा निर्देश जो कि इस खनन पट्टे पर समय-समय पर दिये जाये लागू होंगे।
10. अनुमोदित खनन योजना किसी भी प्रभावी माननीय न्यायालय, मा० ट्रिब्यूनल एवं किसी प्रकार के अन्य न्यायालय आदि के आदेश एवं दिशा निर्देश के लागू होने को बाधित नहीं करती है।
11. इस खनन योजना एवं उत्तरोत्तर खान बन्द करने की योजना का अनुमोदन किसी भी न्यायालय के सक्षम क्षेत्राधिकार के किसी आदेश या निर्देश पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किया गया है।
12. प्रत्येक छाई में खनन क्षेत्र की अनुमोदित खनन योजना के अनुसार आकलन जिला खान अधिकारी भूत्त्व एवं खनिकर्म को आंकलन आख्या प्रस्तुत की जानी होगी।
13. धातिक खनन अधिनियम 1961 के अनुसार खदान सुरक्षा, खदान में कार्यरत श्रमिकों की सुरक्षा एवं स्वारक्ष्य की सम्पूर्ण जिम्मेदारी पट्टाधारक की होगी।
14. खनन योजना एवं उत्तरोत्तर खान बन्द करने की योजना का निष्पादन/क्रियान्वयन निषेधाज्ञाओं/अधिसूचनाओं, आदि कोई हो तो के रिक्त होने के अधीन होगा।
15. आवेदक जिस खेत में कार्य करेगा उस खेत की सूचना सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी/जिला खान अधिकारी, एवं सम्बन्धित तहसील के उपजिलाधिकारी के कार्यालय को जिस खेत में खनन हो रहा है के भूस्वामी से किये गये अनुबन्ध की छाया प्रति खनन कार्य प्रारम्भ करने के 15 दिन पूर्व प्रस्तुत करेगा।
16. भू-सदर्भित खनन पट्टा प्लान्स सम्मिश्रण उपरान्त भू-संदर्भित वैक्टोरोइज्ड खसरा प्लान से पूरी तरह मेल होना चाहिए इसके त्रुटीपूर्ण होने की दशा में सम्बन्धित आर०क्यू०पी तथा आशयपत्र धारक जिम्मेदार होंगे।
17. अनुमोदित खनन योजना एवं उत्तरोत्तर खान बन्द करने की योजना की स्कैन प्रति सम्बन्धित जिलाधिकारी कार्यालय, जिला खान अधिकारी, भूत्त्व एवं खनिकर्म इकाई, सम्बन्धित उपजिलाधिकारी एवं आवेदक को अभिलेखार्थ यथाशीघ्र प्रस्तुत करने का दायित्व सम्बन्धित आर०क्यू०पी०/आवेदक का होगा।

संलग्नक: खनन योजना

एवं उत्तरोत्तर खान बन्द करने की योजना
की अनुमोदित प्रति।

३५५२] (एस० एल० पैट्रिक)
निदेशक।

संख्या /मु०ख०/खनन/77/सोपस्टोन/बाग०/भू०खनि०ई०/2016-17, तददिनांकित

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. सचिव, खनन, उत्तराखण्ड शासन।
2. जिलाधिकारी, बागेश्वर।
3. सदस्य सचिव राज्यस्तरीय पर्यावरण समाधात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) उत्तराखण्ड देहरादून।
4. जिला खान अधिकारी, खनन, भूत्त्व एवं खनिकर्म इकाई, बागेश्वर।
5. श्री कान्ती लाल साह पुत्र श्री गिरधारी लाल साह, निवासी पिण्डरी रोड, तहसील व जिला बागेश्वर।
6. श्री पंकज पाण्डे, आर०क्यू०पी०, पंजीकरण संख्या मु०ख०/आर०क्यू०पी०/डी०डी०एन०/04/2016।

✓ (एस० एल० पैट्रिक)
निदेशक।